

दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काड़ी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

बीड (महाराष्ट्र)

वर्ष - 1 ला

अंक - १४५ वा

मंगलवार २४ दिसंबर २०२४

RNI TITLE CODE : MAHHIN11405/120/1/3/2024

किमत २ रुपये

पन्ने - ४

केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी हूवे थे नाराज



एस पी बारगळ पर हक्कभंग के प्रस्ताव पर सांसद बजरग सोनावने कि तामीर से गुफ्तगू

बीड (तामीर न्यूज)

सरपंच का खुन और लाचार कानून कि दास्तान बीड के सांसद बजरग सोनावने ने जब देश के गृह मंत्री अमित शाह को सूनाई तो वो भी नाराज और भावुक हो गए थे।

और मैं तो एस पी बारगळ के असहयोग के कारण निराश हो चला था लेकिन फिर सूरिया ताई सूले के साथ सांसद ने आवाज बुलंद किया जिस के बाद और लोगों का भी समर्थन मिला और फिर महाराष्ट्र के विधान सभा में भी इस कि गुंज रही। इस तरह के प्रतिक्रिया सांसद बजरग सोनावने ने तामीर से बात करते हूवे दि। सोनावने के मुताबिक एस पी ने फोन नं उठा कर मुझ से ज्यादा लोकशाही और लोकप्रतिनिधि का अपमान किया था। याद रहे कि 9 दिसंबर को मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख का अपहरण हुआ। इस घटना के दौरान सांसद बजरग सोनावने ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) अविनाश बारगळ से तुरंत जांच शुरू करने के लिए संपर्क करने की पूरी कोशिश की। लेकिन, एसपी बारगळ ने कथित तौर पर राजनीतिक दबाव के चलते सांसद के फोन और संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया। इस घटना को लेकर सांसद सोनावने ने 12 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष के पास एसपी के खिलाफ हक्कभंग प्रस्ताव दर्ज कराया। 18 दिसंबर को गृह मंत्रालय के हक्कभंग और नैतिकता विभाग के उपसचिव ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सुजाता सौनिक को एक पत्र भेजकर इस मामले में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।



एसपी के लिए क्या खतरा है?

यह स्पष्ट हो चुका है कि एसपी बारगळ ने राजनीतिक दबाव के कारण सांसद बजरग सोनावने के कॉल और संदेशों का जवाब नहीं दिया। यह लापरवाही अब उनके खिलाफ जा सकती है, और उन पर कड़ी कार्रवाई की संभावना है। यह एक ऐसा औपचारिक प्रस्ताव है जिसे किसी सांसद या विधायक द्वारा तब पेश किया जाता है, जब उन्हें लगता है कि उनके विशेषाधिकारों (Privileges) का उल्लंघन किया गया है। ये विशेषाधिकार उन्हें उनके कार्य करने में स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं।

क्या हुआ था?

9 दिसंबर को सरपंच संतोष देशमुख के अपहरण की खबर मिलने के बाद सांसद बजरग सोनावने ने एसपी अविनाश बारगळ को बार-बार फोन और संदेश भेजे। सांसद ने अपहरण के मामले में तत्काल कार्रवाई कर सरपंच को बचाने की अपील की। लेकिन एसपी ने इन कॉल और संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया। बाद में यह साफ हुआ कि आरोपी का संबंध राजनीतिक लोगों से था, जिसके कारण एसपी ने जानबूझकर लापरवाही दिखाई।

हक्कभंग प्रस्ताव क्या है?

9 दिसंबर को सरपंच संतोष देशमुख के अपहरण की खबर को सांसद सोनावने ने आरोप लगाया कि 9 दिसंबर को एसपी बारगळ ने सांसद द्वारा किए गए सभी संपर्कों को अनदेखा किया और अपहरण के मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सांसद का यह भी कहना था कि विभिन्न अधिकारियों की सिफारिशों के बावजूद, एसपी ने एक सांसद को उचित सुरक्षा देने में भी लापरवाही बरती। यह सांसद के अधिकारों का उल्लंघन था। सांसद ने इस मामले से जुड़े सभी सबूतों के साथ लोकसभा अध्यक्ष के पास हक्कभंग प्रस्ताव दर्ज कराया। लोकसभा अध्यक्ष ने इस मामले को तुरंत केंद्रीय गृह मंत्रालय के संज्ञान में लाया। इसके बाद, हक्कभंग और नैतिकता विभाग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को 18 दिसंबर को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए।

क्या हो सकती है सजा?

अगर किसी व्यक्ति या अधिकारी को सांसद के अधिकारों के हनन या संसद का अपमान करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे निम्नलिखित सजा दी जा सकती है:

- जेल
- चेतावनी या फटकार
- सेवा से निलंबन या नौकरी से बर्खास्तगी

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव कब आता है?

जब कोई अधिकारी, व्यक्ति या संस्था:

- सांसद या विधायक की बातों को नजरअंदाज करता है।
- उनके कार्य में बाधा डालता है।
- उनकी गरिमा या सम्मान को ठेस पहुंचाता है।
- उनके अधिकारों की अनदेखी करता है।

उदाहरण

यदि कोई सांसद किसी पुलिस अधिकारी से तत्काल कार्रवाई के लिए संपर्क करता है और वह अधिकारी राजनीतिक दबाव या अन्य कारणों से जवाब नहीं देता, तो इसे सांसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। इसके लिए सांसद विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, जिसके बाद जांच और कार्रवाई की जाती है। यह प्रस्ताव संसद या विधानमंडल की गरिमा बनाए रखने और उसके सदस्यों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार सुनिश्चित करता है।

भुजबळ को मुख्यमंत्री फडणवीस ने धैर्य रखने की सलाह दी

सागर बंगले पर 40 मिनट की बंद कमरे में चर्चा

जमीर काजी

मुंबई - मंत्रिमंडल विस्तार में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा नजरअंदाज किए जाने से नाराज एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ ने सोमवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। भुजबळ अपने भतीजे समीर भुजबळ के साथ मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास सागर बंगले पर पहुंचे और वहां लगभग 40 मिनट तक अपनी शिकायतें साझा कीं। अजीत पवार या एनसीपी के अन्य नेताओं से मिलने के बजाय सीधे मुख्यमंत्री फडणवीस से मिलने के उनके फैसले ने राजनीतिक अटकलों को जन्म दिया है। इसे भुजबळ के एनसीपी छोड़ने के इरादे के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, मुख्यमंत्री फडणवीस ने reportedly भुजबळ को 8-10 दिनों तक धैर्य रखने की सलाह दी। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भुजबळ ने कहा, "ओबीसी समुदाय ने विधानसभा चुनावों में महायुती



की शानदार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि सरकार ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होने देगी।" भुजबळ ने मंत्रिमंडल विस्तार में नजरअंदाज किए जाने पर खुलकर नाराजगी जताई है। वह राज्यभर में ओबीसी समुदाय के सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहे हैं ताकि अपनी अगली रणनीति तय कर सकें। भुजबळ लगातार अजीत पवार की आलोचना कर रहे हैं, जिससे उनके एनसीपी छोड़ने की अटकलें और तेज हो गई हैं। इसी पृष्ठभूमि में भुजबळ ने सुबह करीब 10:30 बजे मुख्यमंत्री फडणवीस के सागर बंगले पर उनसे मुलाकात की। अपने भतीजे के साथ, भुजबळ ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी चिंताएं रखीं।

इन्साफ के लिए २८ दिसंबर को मोर्चा, राज्यभर के नेता होंगे शामिल

बीड - स्व. संतोष देशमुख की बेरहमी से की गई हत्या के विरोध में और उनके हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर 28 दिसंबर 2024 को बीड शहर में एक सर्वदलीय, अर्धजातीय, और सर्वधर्मीय विशाल मोर्चा आयोजित किया गया है। यह फेसला बीड के आशीर्वाद लॉन्स में हुई बैठक में लिया गया। इस बैठक में सभी पार्टियों के नेता, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद थे। बैठक की शुरुआत में स्व. संतोष देशमुख को श्रद्धांजलि



दी गई। इसमें मौजूद सभी ने बीड जिले में बढ़ते अपराध और जातिवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही, संतोष देशमुख के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें फांसी देने की मांग को लेकर एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की गई। यह विशाल मोर्चा भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा से शुरू होगा। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे बड़ी संख्या में इस मोर्चे में हिस्सा लें। "न्याय के लिए साथ आएं, अन्याय का जवाब दें।" यही संदेश देते हुए सभी ने इस लड़ाई में शामिल होने का संकल्प लिया है।

'संगीत मानापमान' ने मराठी कला और संगीत को नया जीवन दिया: देवेंद्र फडणवीस

मुंबई - "मराठी संगीत नाटक एक अभिजात कला है। इस कला और संगीत की परंपरा को नई पीढ़ी के सामने एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। फिल्म संगीत मानापमान हमारी समृद्ध मराठी कला और संगीत विरासत को नया जीवन देने की दिशा में एक कदम है," मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संगीत मानापमान फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर यह बात कही। फिल्म का ट्रेलर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अभिनेत्री निवेदिता सराफ, अभिनेता

और फिल्म के निर्देशक सुबोध भावे, अभिनेता सुमीत राघवन, अभिनेत्री वेदेही परशुरामी, अमृता खानविलकर, जियो स्टूडियोज की ज्योति देशपांडे, सुनील फडतरे, निखिल साने और संगीत निर्देशक शंकर-एहसान-लॉय समेत फिल्म के अन्य कलाकार उपस्थित थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने भाषण में कहा, "संगीत मानापमान पिछले 113 वर्षों से मराठी दिलों को आकर्षित कर रहा है। यह देखना आनंददायक है कि इस अमर नाटक को एक नई शैली में फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है।

28 दिसंबर को बीड में संतोष देशमुख हत्या मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन

विशेष संवाददाता

मुंबई - सरपंच संतोष देशमुख की हत्या की निष्पक्ष जांच और मुख्य साजिशकर्ता समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सकल मराठा समाज ने 28 दिसंबर को बीड जिला कलेक्टर कार्यालय तक विरोध मार्च निकालने की घोषणा की है।

यह घोषणा मराठा नेताओं अंकुश कदम और नरेंद्र पाटिल ने सोमवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। संतोष देशमुख की हत्या राज्यभर में चर्चा का विषय बन गई है। नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, जिससे समाज में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया है।

PASBAAN E ADAB & ISLAM GYMKHANA PRESENT

G.M. MOMIN WOMEN'S COLLEGE

KHUSRAU SHANASI

24th DECEMBER 2024 TUESDAY

17:00HRS TO 17:30HRS

CONFERENCE ROOM ISLAM GYMKHANA MARINE LINES, MUMBAI

ENTRY FREE FIRST COME | FIRST SEAT

REGISTERED www.pasbaanecadab.com

CHIEF GUEST **ALAM BASHIR SHAIKH** PUDHARI

SUPPORTED BY:

संजय गांधी और श्रावणबाल योजनाओं के जरिए जरूरतमंदों को मिलेगा सहाय्य बीड के विधायक संदीप क्षीरसागर की मेहनत रंग लाई

बीड : बीड तालुका के कई जरूरतमंद लोगों को अब संजय गांधी निराधार योजना और श्रावणबाल योजना के तहत मदद मिलेगी। लंबे समय से अटकी हुई इन योजनाओं की मंजूरी अब पूरी हो गई है और नए लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है। विधायक संदीप क्षीरसागर ने प्रशासनिक स्तर पर लगातार प्रयास किए, जिससे यह सफलता मिली है।

श्रावणबाल योजना, जो बुजुर्ग और बेसहारा नागरिकों को उनके गुजरने के लिए आर्थिक सहायता देती है, और संजय गांधी निराधार योजना, जो विकलांग, अंध, अनाथ, लंबी बीमारी से पीड़ित लोग, तलाकशुदा महिलाएं और अन्य जरूरतमंदों को मदद देती है, इन योजनाओं पर काफी समय से काम रुका हुआ था। समिति की बैठकें न होने की वजह से गरीब और जरूरतमंद लोग



इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह रहे थे। आवेदन देने के बावजूद लोगों को मंजूरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। विधायक संदीप क्षीरसागर ने प्रशासनिक स्तर पर बार-बार बैठकें कीं और संबंधित समितियों को निर्देश दिया कि वे पात्र लाभार्थियों की नई सूची बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि मदद सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।

श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ति वेतन योजना के तहत, बीड तालुका के ग्रामीण क्षेत्रों से 129 और शहरी क्षेत्रों से 97 आवेदन मंजूर किए गए हैं। इसी तरह, संजय गांधी निराधार पेंशन योजना के तहत ग्रामीण इलाकों से 112 और शहरी इलाकों से 76 पात्र लाभार्थियों को आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। तहसीलदार के नेतृत्व में हुई बैठकों के बाद इन नए लाभार्थियों को योजनाओं

की सूची में शामिल किया गया। इससे लंबे समय से मदद का इंतजार कर रहे गरीब और जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस उपलब्धि में विधायक संदीप क्षीरसागर का अहम योगदान रहा है। साथ ही, उन्होंने अपील की है कि जिन लाभार्थियों के आवेदन में कमी रह गई है, वे जल्द से जल्द अपनी त्रुटियां सुधारें ताकि वे भी इन योजनाओं का लाभ ले सकें।

अगर राशन दुकानदार पैसे मांग रहा हो, तो तहसीलदार या मुझसे संपर्क करें - आलम

बीड (प्रतिनिधि): बीड शहर के राशन दुकानदारों का व्यवहार कब कैसा होगा, यह कहा नहीं जा सकता। समय पर राशन नहीं देना, देने पर नियमों का पालन न करना, और राशन कार्ड धारकों से बदतमीजी से बात करना आम हो गया है। अब तो केवाईसी के नाम पर कार्ड धारकों से 100 रुपये वसूलने की लूट शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, राशन निकालने के लिए केवाईसी के बहाने लोगों के अंगूठे का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास बात यह है कि दिसंबर महीने के राशन का ट्रांजेक्शन भी किया जा रहा है, लेकिन लाभार्थियों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। यह सवाल उठ रहा है कि जिनका ट्रांजेक्शन हो चुका है,



क्या उन्हें दिसंबर का राशन मिलेगा या नहीं? इस पर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान जाएगा या नहीं? बीड के राशन दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। अपनी मर्जी से नए-नए नियम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।

गरीब लाभार्थियों को भ्रमित कर केवाईसी के नाम पर राशन हड़पने का गोरखधंधा चल रहा है। जबकि सरकार की तरफ से केवाईसी मुफ्त है, फिर भी केवाईसी के नाम पर 100-100 रुपये मांगे जा रहे हैं। इस बारे में जब हमने बीड के तहसीलदार चंद्रकांत शेलके से बात की, तो उन्होंने कहा कि केवाईसी मुफ्त है। इसलिए, नागरिकों से अनुरोध है कि अगर आपका राशन दुकानदार केवाईसी के लिए पैसे मांग रहा हो, तो तुरंत मुझसे (मो. 9822887039 - खुशीद आलम) या चंद्रकांत शेलके (मो. 9595184545) से संपर्क करें। यह अपील राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीड शहर अध्यक्ष और पूर्व सभापति खुशीद आलम ने की है।

मुंबई में 4 साल के बच्चे को SUV ने रौंदा सड़क किनारे खेल रहा था; फैमिली फुटपाथ पर रहती थी

मुंबई : पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किया गया क्रेटा कार चालक नशे में था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। - Dainik Bhaskar
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किया गया क्रेटा कार चालक नशे में था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। मुंबई में 19 साल के क्रेटा चला रहे एक युवक ने 4 साल के बच्चे को रौंदा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना शनिवार शाम को करीब 5 बजे हुई है, तब बच्चा सड़क किनारे खेल रहा था। मृतक बच्चे का नाम आरुष किनवाड़े है। उसकी फैमिली वडाला इलाके में अंबेडकर कॉलेज के पास फुटपाथ पर रहती है। शनिवार को बच्चा फुटपाथ के पास ही खेल रहा था। इसी दौरान तेज

रफ्तार से SUV कार चला रहे युवक ने आरुष पर कार चढ़ा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम भूषण संदीप गोले है। वह विले पार्ले का रहने वाला है। एक्सीडेंट को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। 12 दिन पहले भी मुंबई में BEST बस ने 30 लोगों को कुचला था। पुलिस ने बताया कि आरोपी भूषण संदीप गोले को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल कराया गया है। वह नशे में कार चला रहा था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। बच्चे की बांडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच के बाद ही जानकारी दी जाएगी। मुंबई में 12 दिन पहले बस ने 30 लोगों को कुचला मुंबई के कुर्ला में 8 दिसंबर को BEST बस ने

करीब 30 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें चार की मौत हो गई और 26 लोग घायल हुए। हादसा कुर्ला पश्चिम रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर नगर में हुआ। बस कुर्ला स्टेशन से अंधेरी जा रही थी। देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7.77 लाख मौतें, महाराष्ट्र में 66 हजार देश में पिछले 5 साल में सड़क हादसों में 7.77 लाख मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा 1.08 लाख मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। इसके बाद तमिलनाडु 84 हजार मौत और महाराष्ट्र 66 हजार मौत के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है। अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से जारी किए गए 2018 से 2022 के डेटा के आधार पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने 'रोड एक्सीडेंट इन इंडिया, 2022' रिपोर्ट जारी की है।

जासूसी के शिकार 1400 यूजर्स में शामिल 300 भारतीय; देश में पेगासस पर फिर छिड़ सकती है बहस

नई दिल्ली : भारतीय राजनीति में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर एक बड़ा मुद्दा रहा और अमेरिकी कोर्ट के इजरायली NSO ग्रुप को लेकर आए फैसले के चलते, भारत में एक बार फिर पेगासस विवाद पर बहस छिड़ सकती है। अमेरिकी अदालत ने एनएसओ ग्रुप को पेगासस के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि कंपनी इस पूरे विवाद के लिए जवाबदेह है। अमेरिका कोर्ट का यह फैसला WhatsApp द्वारा NSO ग्रुप के खिलाफ दायर केस में आया है। इस केस को सुनने वाले जज फिलिस हैमिल्टन ने कहा है कि इजरायली स्पाईवेयर निर्माता 1400 वॉट्सएप यूजर्स को टारगेट करने के लिए आरोपी है। जज ने कहा कि यह अमेरिकी कानून का उल्लंघन करने के लिए NSO ग्रुप भी उत्तरदायी है। भारत में भी पेगासस के जरिए जासूसी का आरोप



पेगासस के इस्तेमाल के शिकार लोगों की बात करें तो इसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनीतिक असंतुष्ट और राजनयिक शामिल हैं। भारत में पेगासस कथित तौर पर पत्रकारों, राजनेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और कुछ सामाजिक सदस्यों के डिजिटल गैजेट्स में लगाया गया था। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के

प्रशासन ने 2021 में NSO समूह को ब्लैक लिस्ट सूची में डाल दिया और अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को इसके प्रोडक्ट्स खरीदने से रोक दिया था। आरोप है कि पेगासस को इस्तेमाल दुनियाभर के देशों में सत्ताधारी सरकारों की पार्टियों ने हैकिंग और जासूसी के लिए किया है। भारत को लेकर 2021 में हुआ था खुलासा साल 2021 में एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था कि पेगासस का उपयोग 300 से अधिक भारतीय मोबाइल नंबरों पर भी किया गया था। इनमें नरेंद्र मोदी सरकार के दो मंत्री, तीन विपक्षी नेता, एक संवैधानिक प्राधिकरण, कई पत्रकार और व्यवसायी शामिल थे। इस खुलासे ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर सवाल खड़े कर दिए। आईफोन फिर पेगासस का खतरा? केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों की

सरकारों पर आरोप इसलिए भी लगाए गए क्योंकि एनएसओ ग्रुप ने बार-बार स्पष्ट तौर पर यह कहा कि वह केवल सरकारों और सरकारी एजेंसियों से ही डील करता है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्हाट्सएप बनाम एनएसओ ग्रुप मामले के हिस्से के रूप में बिना सील किए गए दस्तावेजों से पता चला है कि एनएसओ ग्रुप ने सालों तक पेगासस की तेनाती में अपनी भूमिका को कम करके आंका था। भारत सरकार ने किया था आरोपों का खंडन 2021 की मीडिया रिपोर्ट्स के बाद भारत सरकार ने पेगासस के इस्तेमाल के दावों का खंडन किया और कहा कि वह किसी भी तरह की जासूसी में शामिल नहीं है। उस समय संसद में दिए गए एक बयान में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रिपोर्टों में कोई तथ्य नहीं है। आईटी मंत्री ने कहा कि भारत के

इतना बवाल हुआ, 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा... विंटर सेशन में सबसे कम चली संसद

नई दिल्ली : संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे के साथ खत्म हो गया, हैरानी की बात यह रही कि इस बार काम इतना कम हुआ कि 10 सालों का सीधे रिकॉर्ड टूटा। पीएम मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, इस बार संसद की सबसे कम प्रोडक्टिविटी देखने को मिली। बड़ी बात यह है कि ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड तब बना है जब इसी साल मानसून सेशन उतना ही बेतहीन काम देखने को मिला था। इन्होंने नेताओं ने कई घंटों तक संसद को चलाया और कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। PRS Legislative Research के आंकड़े अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि पिछले 10 सालों में इस बार लोकसभा और राज्यसभा सबसे कम चली है। इस बार लोकसभा की प्रोडक्टिविटी मात्र 52 फीसदी दर्ज की गई है, दूसरे शब्दों में बोले तो 62 घंटे। पिछले

10 सालों में सिर्फ 8 और ऐसे सत्र देखने को मिला है जहां काम ना के बराबर देखने को मिला। संसद में कितना काम हुआ? वैसे जो इस साल बजट सेशन हुआ था, तब 135 प्रतिशत की अप्रत्याशित प्रोडक्टिविटी देखने को मिली, यानी कि 115 घंटे के करीब संसद ने काम किया। अगर उन आंकड़ों से इस बार की तुलना की जाए तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। राज्यसभा की बात करें तो वहां भी इस बार मात्र 44 घंटे काम हुआ है, जिसे सिर्फ 39 फीसदी माना जाएगा। मानसून सत्र में तो राज्यसभा में 93 घंटे काम हुआ था, 112% की प्रोडक्टिविटी दर्ज की गई थी। इस सत्र में सबसे कम बिल भी पारित होते दिखे। सरकार ने पांच बिल पेश किए, लेकिन चार ही पारित हो पाए। पिछले पांच सालों में

यह सबसे खराब प्रदर्शन रहा। इस बार की संसद 25 नवंबर को शुरू हुई थी, 29 नवंबर तक सिर्फ 40 मिनट की कार्यवाही हुई, यानी कि 4 दिनों में सिर्फ 40 मिनट। इसी तरह अगर 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक का हाल देखें तो फिर बवाल ही ज्यादा रहा और काम ना के बराबर। आखिर के चार दिनों में संविधान पर बहस हुई, एक देश एक चुनाव बिल पेश हुआ और धक्का मुक्की वाले कांड ने विवाद खड़ा किया। जब संसद नहीं चलता, कितना नुकसान? असल में यह जो संसद की कार्यवाही चली है, हर मिनट ढाई लाख खर्च हो रहा है। एक घंटे के हिसाब से देखें तो 1.5 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो जो सारा पैसा संसद चलाने में इस्तेमाल हो रहा है, वो आम जनता के टैक्स का पैसा है।

राहुल गांधी को जाति जनगणना के मुद्दे पर आया कानूनी नोटिस

नई दिल्ली : राहुल की निचली अदालत ने बड़ाई मुश्किल (Photo: ANI) Rahul Gandhi News: लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Chunav 2024) के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने जाति जनगणना का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था। कांग्रेस (Congress) को इसका फायदा भी मिला। अभी भी राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना (Caste Census) के मुद्दे पर बयान देते रहे हैं। इस बीच बरेली कोर्ट

(Bareilly Court) ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है और 7 जनवरी को पेश होने की बात कही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बरेली कोर्ट ने जारी नोटिस पर कांग्रेस पार्टी (Congress) भड़क गई है। कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद उदित राज (Udit Raj) ने तो यह तक कह दिया है कि ऐसे जजों को तुरंत ही बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर क्या कहा? राहुल गांधी के जातिगत

जनगणना के मुद्दे पर याचिकाकर्ता पंकज पाठक ने कोर्ट का रुख किया और कहा कि हमें लगा कि जाति जनगणना पर चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान देश गृहयुद्ध शुरू करने की कोशिश जैसा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हमने पहले MP-MLA कोर्ट में उनके खिलाफ मामला दायर किया था, जिसका खारिज कर दिया गया था। उसके बाद वे जिला जज कोर्ट गए वहां हमारी अपील स्वीकार कर ली गई।

जयपुर हादसे में झुलसे हुए 30 लोगों के लिए सीढ़ी बनी लाइफलाइन

नई दिल्ली : राजस्थान के जयपुर में टैंकर से एलपीजी रिसाव की वजह से आग लगने के बाद जले हुए 30 पीड़ितों ने जयपुर-अजमेर हाईवे से सटे एक फार्माहाउस में शरण ली थी। खेत के बीच में एक अस्थायी घर में रहने वाले परिवार ने मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें सुनीं। इसके बाद उन्होंने अपने घर के गेट खोले और बाहर का डराने वाला मंजर देखा। परिवार के मुखिया भंवर लाल ने टॉइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'वे कपड़े, पानी और अपने दर्द को कम करने के लिए कुछ मांग रहे थे।' उन्होंने आगे बताया कि उनकी स्किन जल गई थी और

उनमें से कई के मुंह में से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। कंडोई अस्तपाल करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए खेत और आठ फीट की दीवार को पार करके जाना पड़ता। आग में झुलसे लोग गंभीर तरीके से घायल थे और उनके लिए दीवार को पार करना आसान नहीं लग रहा था। तभी किसान परिवार के एक सदस्य राकेश सैनी ने मदद करने की ठानी। उसने एक सीढ़ी को लिया और दीवार के सहारे टेक दिया। इस सीढ़ी की वजह से पीड़ितों को नई जिंदगी भी मिली।

लोग दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहे थे सैनी ने बताया, 'मैंने कम से कम 30 लोगों को आग की लपटों से भागते हुए हमारे खेतों की ओर जाते देखा। वे दर्द से कराह रहे थे और बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। इतना ही नहीं उनके कपड़े भी जल चुके थे। मैंने बिना सोचे समझे सीढ़ी उठा ली।' हालांकि, सैनी को एहसास हुआ कि कई लोग इतने कमजोर थे कि वे खुद सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकते थे। एक-एक करके उन्होंने उन सभी को सीढ़ी पर चढ़ने में और दीवार को फांदने में मदद की। छोटी सी पोतली में समा गया शरीर, DNA सैपल से हो रही पहचान